भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-148
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

झारखंड और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता

†148. **श्री मनीष जायसवाल:**
श्री लुम्बा राम:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दुलू महतोः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों के समक्ष आने वाली बाधाओं और रुकावटों का आकलन किया है/कर रही है;
(ख) इन राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में, विशेषकर झारखंड राज्य सरकार के लिए कोई दिशानिर्देश/निर्देश दिया गया है;
(घ) क्या राज्यों में सामाजिक-आर्थिक असमानताएं बच्चों के शैक्षिक अवसरों और परिणामों को प्रभावित करती हैं; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रभाव के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना, राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन,

स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि शामिल हैं।

समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरूआत, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान तथा छात्र विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता और नवाचार का एक समर्पित घटक है, जिसमें छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिसके तहत झारखंड और राजस्थान सहित राज्यों को समग्र प्रगति कार्ड, पुस्तकालय, कौशल प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता, कौशल शिक्षा के लिए प्रशिक्षुता, छात्र/शिक्षक डायरी आदि जैसी पहलों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) समग्र शिक्षा योजना का अभिन्न अंग हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने और शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और डीआईईटी का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

राजस्थान और झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत) को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि देश में प्रत्येक बच्चा आवश्यक रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त करें, और उक्त हेतु ई-सामग्री दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है।
ii. शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों/प्रधानाचार्यों, मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
iii. विद्या प्रवेश- 29 जुलाई, 2021 को कक्षा-1 के बच्चों के लिए तीन माह के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि सभी बच्चे जब अपनी ग्रेड-1 की कक्षा में आएं तो उन्हें एक हंसता-खेलता और प्यार भरा वातावरण मिले।
iv. समग्र शिक्षा के तहत, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षण-अधिगम सामग्री जैसी पहलों तथा अधिगम अंतरालों की पहचान करके और विशेष ग्रेड के लिए मुख्य अधिगम पूर्वापेक्षाओं हेतु छात्रों को तैयार करके समग्र प्रगति कार्ड और अधिगम संवर्द्धन कार्यक्रम जैसी अधिक प्रगतिशील पहलों को कार्यान्वित किया जाता है।

v. मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एसई) जारी कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 1 एवं 2 के लिए एनसीएफ एफएस पर आधारित पाठ्यपुस्तकें और कक्षा 3 एवं 6 के लिए एनसीएफ एसई पर आधारित पाठ्यपुस्तकें जारी कर दी गई हैं।

उपरोक्त पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक बैठकों और राज्यों द्वारा प्रबंध पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए डेटा के माध्यम से की जा रही है।

झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद सहित सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सीएम उत्कृष्ट विद्यालय (हजारीबाग-4, रामगढ़-3, धनबाद-3) स्थापित किये गये हैं।
- ब्लॉक स्तरीय लीडर स्कूल (हजारीबाग-19, रामगढ़-6, धनबाद-17**)** स्थापित किए गए हैं।
- राज्य के सभी जिलों में राज्य द्वारा भाषा मैपिंग अभियान आयोजित किए गए।
- सभी जिलों में कक्षाओं में छात्रों को सार्थक रूप से नियोजित करने के लिए विभिन्न पठन और खेल सामग्री के साथ कक्षाओं को समृद्ध किया गया।
- राज्य भर में बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए साप्ताहिक टेस्ट (आरएआईएल) शुरू किया गया।
- राज्य के सभी जिलों में एफएलएन के तहत व्यापक पठन संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और मूलभूत शिक्षण अध्ययन (एफएलएस) में हजारीबाग, धनबाद और रामगढ़ सहित राज्य के सभी जिलों ने भाग लिया। बेंच-डेस्क, बिजली, शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय, कक्षाओं आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कमियों का विश्लेषण किया गया और कमियों को पूरा करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा तक पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक-आर्थिक अंतराल को कम करने का प्रावधान किया गया है। समावेशी, न्यायसंगत और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****